दिसंबर, 2019

किन्नर (transgender) समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में खोला जाएगा।

यह अपने सदस्यों को कक्षा एक से स्नातकोत्तर तक सही अध्ययन करने और यहां तक कि शोध करने और पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। विश्वविद्यालय अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट (अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर शिक्षा सेवा ट्रस्ट) द्वारा बनाया जा रहा है।

5 एएसआई संरक्षित पुरातात्विक स्थलों पर चीनी भाषा में साइन बोर्ड लगाए गए हैं

केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित पांच एएसआई संरक्षित पुरातात्विक स्थलों पर चीनी भाषा में साइन बोर्ड लगाए गए हैं। उनमें सारनाथ, बौद्ध अवशेष चौखंडी स्तूप, कुशीनगर और महापरिनिर्वाण मंदिर, पिपरहवा और श्रावस्ती शामिल हैं। जहां हर साल एक विशेष देश के एक लाख से अधिक पर्यटक आते हैं वहां विदेशी भाषाओं के साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। कुल पांच ऐसी विदेशी भाषाओं को इसमें शामिल किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षा उद्योग के लिए 25% अनुदान और पूर्ण स्टाम्प शुल्क माफ करने की घोषणा की

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में रक्षा उद्योग स्थापित करने के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी और 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क माफी प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य में रक्षा उद्योग स्थापित करने वाली कंपनियों को बिजली, सड़क और जमीन की बाड़ लगाने सहित सभी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 218 फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की मंजूरी दी

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बच्चों और बलात्कार के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए 218 फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन फास्ट-ट्रैक अदालतों के लिए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के 218 पद सृजित किए गए हैं और अदालत के लिए कर्मचारी पद भी सृजित किए जाएंगे।

ये विशेष अदालतें कुल 1,023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FCSs) का हिस्सा होंगी, जिन्हें POCSO संशोधन अधिनियम 2019 के तहत स्थापित करने का प्रस्ताव था। यह बलात्कार के मामलों के त्वरित परीक्षण के लिए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की

कानपुर, उत्तर प्रदेश में 14 दिसंबर, 2019 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय गंगा परिषद (गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद) की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इस परिषद को गंगा और उसकी सहायक नदियों सहित गंगा बेसिन के प्रदूषण निवारण और कायाकल्प की दिशा में प्रयासों की देखरेख और समन्वय के लिए समग्र जिम्मेदारी दी गई है।

महत्वपूर्ण बिंदु :

- प्रधानमंत्री मोदी ने 'स्वच्छता', 'अविरलता' और 'निर्मलता' पर तीन केंद्रित फोकस पर जोर दिया।
- एक समग्र प्रक्रिया की आवश्यकता है जहां 'नमामि गंगे' गंगा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ 'अर्थ गंगा' या एक सतत विकास मॉडल के रूप में विकसित होता है।
- नदी में पर्याप्त और निर्बाध पानी का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने 2015-20 की अवधि के लिए उन पांच राज्यों के लिए 20,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता की थी जिन राज्यों से होकर गंगा गुजरती है।

- प्रधानमंत्री ने डिजिटल डैशबोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया ताकि नीति आयोग और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दैनिक आधार पर गांवों और शहरी निकायों के आंकड़ों की निगरानी की जा सके।